कौन है जिसमें कमी नहीं है,
असमा के पास भी तो जमीन नहीं है।
– अज्ञात

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, लेकिन भरोसेमंद मानी जाने लायक यह अभी ही हो पाई है।

संजय भट्ट

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने एक अद्भुत प्रस्ताव रखा है। उन्होंने अपने देश की सरकारी एजेंसियों से कहा है कि वे अगले साल सिविल सेवा के अधिकारियों की दौ रैंक समाप्त कर दें और उनका काम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए कराएं। इसके पीछे विडोडो का असली मकसद अधिकारियों का बोझ कम करना या सरकारी खर्चे घटाना नहीं है। उनका उद्देश्य है लाल फीताशाही में कमी लाना, जो उनके मुताबिक निवेश के रास्ते में बाधक है।

वैसे दुनिया भर में एआई का इस्तेमाल खर्चा बचाने के लिए ही किया जा रहा है। जो काम अब तक पूरे–पूरे विभाग के जिम्मे हुआ करते थे, उन्हें अब एआई के जरिये निपटाया जा रहा है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, लेकिन भरोसेमंद मानी जाने लायक यह अभी ही हो पाई है। गलतियों के जरिये सीखने का यह कंप्यूटर सिस्टम उन्हीं तर्कों के आधार पर काम करता है, जिनसे मानव मस्तिष्क चलते हैं। एआई ने रोबॉटिक्स को पूरी तरह बदल दिया है। रोबॉट में अब तकनीक के चलते नया सीखने की क्षमता आ गई है। अब वह बहुत से फैसले खुद भी ले सकता है। ज्यों–ज्यों एआई का दायरा बढ़ रहा है, दुनिया भर में बहस तेज होती जा रही है कि यह मनुष्यता के लिए उपयोगी है या घातक?

एक तबका मानता है कि यह तमाम वर्कर्स की जगह ले लेगा और उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ देगा, लेकिन दूसरी राय है कि इसकी वजह से कई नए रोजगार पैदा भी होंगे। आम राय है कि एआई के मजबूत होते जाने के साथ ही ड्राइवर से लेकर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को बड़ी संख्या में नौकरियां खोनी पड़ेंगी। अधिक मानसिक क्षमता वाले काम भी इससे प्रभावित होंगे जिससे डॉक्टर, जर्नलिस्ट और वकालत से जुड़ी नौकरियों पर भी खतरा बढ़ेगा। लेकिन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक एआई अगले कुछ सालों में जितने रोजगार खत्म करेगा उससे कहीं ज्यादा नए रोजगार पैदा करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक इंसान का आधे से ज्यादा काम (करीब 52 फीसदी) मशीनें करने लगेंगी। अभी हमारे कुल काम का केवल 29 फीसदी मशीनें करती हैं। जब मशीनें इंसानों से ज्यादा काम करने लगेंगी तो पूरी दुनिया में 7.5 करोड़ लोगों को नौकरियां खोनी पड़ेंगी, लेकिन एआई के कारण 13.3 करोड़ नई नौकरियां भी आएंगी। ऐसे में जितनी जॉब जाएंगी उससे 5.8 करोड़ ज्यादा नई नौकरियां मार्केट में आ जाएंगी। सबसे तेज बढ़ने वाली नौकरियां होंगीं– डिवेलपर्स, ई–कॉमर्स और सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट की। जाहिर है, रोजगार खास तकनीकी विशेषज्ञता वाले लोगों को ही मिल सकेगा। बहरहाल, अभी तो इंडोनेशिया के अफसरों और ऐसे ही कुछ और काम करने वालों को एआई के कारण बेरोजगारी ही झेलनी पड़ेगी।

प्रकृति के साथ

टीएनएन

धर्म-दर्शन

हम अपने बगीचे की देखभाल करते हैं और जरूरतमंदों के साथ, समय और कभी–कभी अपने संसाधन भी खर्च कर सकते है। हम अब फूलों की बहुत सारी किस्मों के अलावा, नियमित रूप से अमरूदों और पपीतों का आनंद लेने में सक्षम हैं। आम के छोटे पेड़ 15 इंच लंबी पत्तियों के साथ लगभग 12 फुट ऊंचे हैं। हम, अब से कुछ वर्षों बाद हापूस आमों को चखने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली सर्दियों में, हमारा बेटा कश्मीर से कुछ सेब के पौधे लाया और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे जलवायु के परिवर्तन से तालमेल बिठाते हुए जीवित रहें और कुछ साल बाद उनमें फल लगें।

प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। मासूम पक्षी और पेड़ सह–अस्तित्व का एक अच्छा उदाहरण हैं।

संपादकीय

बीएसएनएल का संकट

पब्लिक सेक्टर की टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल का वित्तीय संकट बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। कंपनी के पास अपने 1 लाख 76 हजार कर्मचारियों को जून की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसके लिए उसने सरकार से 850 करोड़ रुपये मांगे हैं। छह महीने के भीतर दूसरी बार ऐसी नौबत आई है। इससे पहले कर्मचारियों को फरवरी की सैलरी मार्च के तीसरे हफ्ते में मिली थी। पिछले कई सालों से बीएसएनएल के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन उसकी आमदनी बढ़ने के बजाय घटती जा रही है।

बताया जा रहा है कि अभी उस पर करीब 13 हजार करोड़ रुपये की देनदारी चढ़ी हुई है। दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल से सभी तरह के ठेके और खरीदारी के ऑर्डर जारी करने का काम रोक देने को कहा है। पिछले हफ्ते कंपनी के इंजीनियरों और लेखा पेशेवरों के एक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपनी के पुनरुद्धार के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि बीएसएनएल पर कोई कर्ज नहीं है और इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ रही है, ऐसे में कंपनी को फिर से खड़ा किया जाना चाहिए। साथ ही जो कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, कंपनी में उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। दरअसल दूरसंचार क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने के बाद से बीएसएनएल तकनीकी मामलों में उनसे पिछड़ती गई। फिर साल 2016 में जियो के आने के बाद से टेलिकॉम कंपनियों में डेटा पैक और टैरिफ सस्ता करने की जो जंग छिड़ी, उसमें कई निजी टेलिकॉम कंपनियां बाजार छोड़ने पर मजबूर हो गईं और बीएसएनएल की तो कमर ही टूट गई। साल 2018 में कंपनी को करीब 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकार के लिए भी लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है क्योंकि सरकार से उम्मीद बांधे रहने की अब उन्हें कोई वजह नहीं दिखती।

चमकी का अंधेरा

नेहा जोशी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण और स्वास्थ्यप्रद वातावरण लोगों के बुनियादी अधिकारों में शामिल है, और यह उन्हें मिलना ही चाहिए। कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एईएस (चमकी बुखार) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने केंद्र और बिहार सरकार से 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है और यह स्पष्ट करने को कहा है कि अब तक इस बीमारी से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए। उसने तीन बिंदुओं पर विशेष रूप से जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है– जन स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता, बच्चों का पोषण और प्रभावित क्षेत्रों में साफ–सफाई की स्थिति। उसने यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया है क्योंकि कुछ समय पहले वहां भी इसी तरह बच्चे बड़ी संख्या में बीमारी के शिकार हुए थे। कैसी विडंबना है कि हमारे देश में कार्यपालिका को उसके कर्तव्यों की याद बार–बार न्यायपालिका को दिलानी पड़ती है।

स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकार के लिए भी लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है क्योंकि सरकार से उम्मीद बांधे रहने की अब उन्हें कोई वजह नहीं दिखती। जहां तक बिहार का प्रश्न है तो वहां चमकी बुखार से डेढ़ सौ से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। बुखार के कारणों को लेकर डॉक्टरों में एक राय नहीं है। बड़े पैमाने पर इसके भड़क उठने के कारण एक झटके में इसे रोकना भी संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से यह बीमारी थोड़े–थोड़े अंतराल के बाद फैल रही है, उससे इस संबंध में सरकारी तैयारियों की कमी का पता तो चलता ही है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई समस्या बार–बार आ रही है तो उसे लेकर विशेष प्रॉजेक्ट चलाए जाने चाहिए थे। बिहार ही नहीं, यूपी के गोरखपुर और आस–पास के जिलों में भी मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप होता रहता है लेकिन वहां भी इससे निपटने के दूरगामी उपाय नहीं किए गए, जिससे पिछले साल अगस्त में कई बच्चों की मौत हो गई। ये हादसे जन स्वास्थ्य को लेकर सरकार के उदासीन रुख को दर्शाते हैं।

दरअसल देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में दोहरी व्यवस्था चल रही है। हेल्थ सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल देने के बाद सरकार की चिंता हेल्थ बीमे तक सिमट गई है। देश का संपन्न और मध्यवर्गीय तबका स्वास्थ्य के लिए सरकारी तंत्र पर निर्भर नहीं है इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने का कोई खास दबाव भी सरकार पर नहीं है। स्वास्थ्य कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता। खस्ताहाल सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर गरीब लोग भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वोट नहीं देते। हां, पार्टियां घोषणापत्रों में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने का दावा जरूर करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता में आने के बाद इस बारे में कोई उनसे सवाल नहीं करने वाला। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। देश की एक बड़ी आबादी को बीमारी और कुपोषण के अंधेरे में छोड़कर हम विकसित देश बनने का स्वप्न नहीं देख सकते।

अष्टयोग-4889

1	5			2		6
	30	7	31		34	
6	3		4		7	1
	37	6	33	6	29	
7	5			1		4
	30		32	7	34	
4	2	1		3	5	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4888 का हल

6	5	4	3	2	7	1
2	34	7	30	4	28	2
7	2	1	6	3	5	4
3	31	6	32	6	33	5
4	5	3	6	1	2	7
5	28	5	33	7	38	3
1	3	2	4	5	7	6

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

अपने ही बो रहे भाजपा की राह में शूल!

लिमटी खरे। भारतीय जनता पार्टी ने दो सीट से केंद्र में सरकार बनाने तक का सफर तय किया है। कई सूबों में भाजपा की सरकार रही है। इक्कीसवीं सदी के पहले दशक तक भाजपा के आला नेताओं का नियंत्रण पार्टी पर जबर्दस्त माना जा सकता है, किन्तु दूसरे दशक में भाजपा की अग्रिम पंक्ति को छोड़कर निचली पंक्तियों में उच्चश्रृखलता जमकर हावी होती दिख रही है। भाजपा को चाल चरित्र और चेहरा वाली आदर्श पार्टी माना जाता रहा है, किन्तु लगातार ही जिस तरह के कदमताल भाजपा की सरकार और उसके प्रतिनिधि करते दिख रहे हैं उसे देखकर यही लगने लगा है कि संगठन में अब आदर्श को बलाए ताक ही रख दिया गया है। ताजा मामला भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का है, जिन्होंने नाथू राम गोडसे को एक बार फिर देशभक्त कहकर भाजपा के आला नेताओं को सोचने पर मजबूर करते हुए नई बस का आगाज कर दिया गया है। भाजपा की भोपाल से संसद सदस्य साधवी प्रज्ञा का विवादों से गहरा नाता रहा है। उनके द्वारा बोली गई बातों पर अक्सर ही विवाद खड़े होते रहे हैं।